

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013—चैत्र 17, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक/पं.ग्रा.वि.वि./22/04/73/2013/158.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.ग्रा.वि.वि./22/04/73/2012/248, दिनांक 09 अप्रैल 2012 द्वारा राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण की निधि के उपयोग के लिए बनाये गये निधि नियम 2012 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 3 के उपनियम (1) से (6) तक को लोप किया जाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित उप नियम (1) से (5) प्रतिस्थापित किया जाये :—

- “(1) माननीय सदस्यों/क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप राशि प्राधिकरण/प्राधिकरण के अध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात्, प्राधिकरण प्रकोष्ठ द्वारा संचालक, पंचायत विभाग को वित्तीय स्वीकृति की संसूचना प्रेषित करते हुए संबंधित जिला कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा.
- (2) प्राधिकरण प्रकोष्ठ से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के आधार पर कलेक्टर द्वारा नियत की गई एजेंसी, प्ररूप-क में विकास कार्यों का विवरण दत्त हुए, प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा. इसमें कार्य का तकनाका स्वीकृति भां सक्षमता अनुसार साम्यालत हागा. कलेक्टर को एक करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार होगा. इसके ऊपर की राशि के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी.

- (3) निर्माण एजेंसी के द्वारा प्ररूप-क में प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेज, ड्राईंग, साईट प्लान, भौतिक सीमा चिन्ह, नक्शा व खसरा (पांच साला) सहित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (4) जिला कलेक्टर निर्माण एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत प्ररूप-क एवं संलग्न आवश्यक दस्तावेजों का पूर्ण परीक्षण करते हुए प्ररूप "ख" में प्रमाण पत्र जारी करेगा. इसमें कार्य की सक्षमता अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति भी सम्मिलित होगी.
- (5) स्वीकृत कार्यों के लिए तैयार प्रस्ताव प्ररूप "क/ख" का संधारण जिला स्तर पर जिला कलेक्टर संबंधित कार्यालय में एक प्रकोष्ठ बनाकर करेंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, सचिव.